खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर

केन्द्र सरकार अनाज से इतर अन्य खाद्य उत्पादों की मदद से कृषि निर्यात बढ़ाने की नीति तैयार कर रही है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करनेवाला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने फल-सब्जी, प्रोसेस्ड फूड्स एवं अन्य जीव-जंतु की मदद से बने ऐसे 20 प्रकार के खाद्य उत्पादों की पहचान की है, जिनके निर्यात में बढ़ोतरी की बड़ी संभावना हो सकती है। इस काम के लिए एपीडा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भी मदद ले रहा है। अब तक 119 एफपीओ निर्यातक बन भी चुके हैं। इससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विमलेश तिवारी | राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर लिखने वाले स्वतंत्र पत्रकार।

देश के किसानों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के फल और सब्जियों की मांग वैश्विक बाज़ार में लगातार बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से फरवरी के दौरान भारतीय फल-सब्जी के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से उन राज्यों के किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है, जहां फल-सब्जी की अधिक खेती की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख फल उत्पादक राज्य हैं। वहीं सब्जियों का उत्पादन करने वाले राज्यों में बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा

शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से तो हरी मिर्च से लेकर दूसरी हरी सब्जियों के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में आलू का निर्यात भी शुरू किया गया है। केले के निर्यात में तो चालू वित्त वर्ष में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक फल और सब्जियों के वैश्विक बाज़ार में अभी भारत की हिस्सेदारी लगभग एक प्रतिशत ही है। इसलिए फल और सब्जी के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। पांच वर्ष पहले तक अधिकतर फल एवं सब्जी का निर्यात एशिया और खाड़ी के देशों तक ही सीमित था। जबकि अब भारत के फलों के खरीदारों में अमरीका और नीदरलैंड जैसे देश भी शामिल हो गए हैं। ब्रिटेन तो भारतीय सब्जियों का मुख्य खरीदार बन गया है। जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों के लिए भारत से अनाज का निर्यात भी शुरू किया जाएगा।

ज़ीरो से हीरो बनने की कहानियां

सरकार से मिल रहे प्रोत्साहन एवं बनाई जा रही नीतियों का ही परिणाम है कि खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र ने ग्रामीण भारत में कई ऐसे उदाहरण पैदा कर दिए हैं, जिन्हें देखकर युवा पीढ़ी अब अपने गांव के संसाधनों में से ही रोज़गार के अवसर तलाश करने लगी है। ऐसा ही एक उदाहरण है पटना के दो भाइयों का। कोरोना काल में निराशा के दौर में दो भाइयों- आनंद सागर एवं आशीष सागर ने हिम्मत जुटाकर फल और सब्जियों की होम डिलिवरी करनी शुरू की थी। आज आम की बिक्री के देश के शीर्ष दस ऑनलाइन प्लेटफार्म में उनकी कंपनी है। इन दोनों भाइयों ने बिहार के दूसरे छोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बड़े बाज़ार की तलाश की और गत तीन वर्षों से वहां बिहार का प्रसिद्ध आम दूधिया मालदह और जर्दालू के साथ-साथ महाराष्ट्र का अल्फांसो, केसर एवं लखनऊ के दशहरी आमों की डोर स्टेप डिलिवरी करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रियां रखने वाले ये दोनों भाई अपने आमों को पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग नहीं करते, ताकि प्राकृतिक रूप से पके आम उपभोक्ताओं को मिल सकें।

इसी प्रकार रायपुर की शुभिका जैन और सुरम्या जैन ने पैतृक व्यवसाय खेती-किसानी से प्रेरणा लेकर कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर सौंदर्य उत्पाद तैयार करती हैं। इनकी कंपनी रिटेल एवं ई-कॉमर्स बिजनेस श्रेणी में फोर्ब्स की प्रतिष्ठित '30 अंडर 30 एशिया' लिस्ट में स्थान बना चुकी है। यह कंपनी लगभग चार हजार किसानों से कच्चा माल सीधे खरीदती है, और उसे प्रसंस्कृत कर अपने उत्पाद तैयार करती है। इस काम की शुरुआत इन्होंने पांच एकड़ के पारिवारिक फार्म में गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा आदि फूलों की खेती से की। इन्होंने कंपनी का पहला उत्पाद फेस ऑयल बनाया था। अब कंपनी के पास लगभग 90 उत्पादन हैं। इन उत्पादों की बिक्री में हर साल तीन से चार गुना वृद्धि हो रही है। इनकी कंपनी के कुल कर्मचारियों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। कंपनी के उत्पाद अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में निर्यात हो रहे हैं। लगभग ऐसी ही कहानी आतंकवाद से पीड़ित जम्मू-कश्मीर के लैवेंडर उत्पादक किसानों की भी है। 2015 से पहले तक यहां के किसान लैवेंडर (एक प्रकार का हल्का बैंगनी फूल) की खेती और उसके उपयोग से अनजान थे। अब जम्मू के डोडा जिले में बड़ी संख्या में किसान लैवेंडर की खेती कर रहे हैं और इसका अर्क बेचकर एक से डेढ़ लाख रुपये प्रतिमाह कमा रहे हैं।

वर्ष 2023-24 में तो परंपरागत कृषि उत्पादों के अलावा कई नए फलों एवं अन्य उत्पादों का भी निर्यात शुरू हुआ है। इनमें बारामती का अमरूद और केला, पूर्वांचल का आलू, मेघालय का खासी संतरा, असम के बींस और नींबू, वाराणसी का सिंघाड़ा और गेंदा फूल, ओडिशा का काजू, उत्तराखंड की ताजी सब्जियां, कर्नाटक का मिक्स्ड अचार और पंजाब का श्रीअन्न शामिल हैं। इन ताजे फलों और सब्जियों के अलावा प्रसंस्कृत उत्पादों में सूखे सूप एवं शोरबा, सॉफ्ट ड्रिंग कॉन्सट्रेंट, सॉस और केचप, पान मसाला, सुपारी, माल्ट, कस्टर्ड पाउडर और नींबू पानी जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। भारत में जैसे-जैसे देशी और विदेशी बाज़ार मिलने की सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे किसान जागरूक हो रहे हैं और उत्पादों में उनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। वे नए-नए उत्पाद तैयार कर रहे हैं, यानी कृषि प्रधान भारत देश के नौजवान और किसान अब अपने कृषि क्षेत्र में ही रोज़गार के अवसर तलाश करने लगे हैं।

बीएआरसी का प्रयास

कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जाती है, क्योंकि अक्सर खेती के उत्पाद या तो इतनी बड़ी मात्रा में तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बाज़ार नहीं मिल पाता। या फिर उनकी इतनी कमी हो जाती है कि पूरे देश में उनकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इस समस्या को दूर करने का एक उपाय होता है कि अधिक उपज के समय ही उन उत्पादों को प्रसंस्कृत कर रख लिया जाए और बाज़ार में उन उत्पादों की कमी के दौर में ये उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध कराए जाएं। इनमें प्याज, टमाटर, अदरक जैसे कई कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत और पैक करके रखा जा सकता है, जिन्हें साल भर बाद तक उपयोग किया जा सकता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) ने अपने 'आकृति' कार्यक्रम के जरिए सौर ऊर्जा से इन खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की तकनीक विकसित की है। आकृति के तारापुर स्थित केंद्र में इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। इस तकनीक को सीखकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा अपने उत्पादों को सहेजकर, उनकी कमी के दिनों में अच्छा लाभ कमा सकते हैं।

चुनौतियां

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इजरायल जैसा छोटा-सा देश जहां तकनीक के बल पर कृषि अपने खाद्य उत्पादों को सहेज लेता है, वहीं भारत जैसे कृषि प्रधान बड़े देश में कृषि उत्पादों को सहेजना आज भी बहुत मुश्किल लक्ष्य लगता है। अनेक सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों का बड़ा वर्ग न तो खाद्य उत्पादों की प्रसंस्करण तकनीक से परिचित है, ना ही उसे बाज़ार मिल पाता है। उसके पास अपना कौशल तो है, लेकिन उस कौशल को तकनीक से जोड़ने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। कृषि उत्पादन निर्यात की सुविधाएं आज भी सागर तटीय राज्यों तक ही सीमित दिखाई देती हैं। पिछले कुछ वर्षों में बनकर तैयार हुए सड़कों और राजमार्गों के बड़े नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश जैसे चारों ओर जमीन से घिरे राज्यों का सागरतटीय राज्यों तक पहुंच आसान कर दी है।

इसके बावजूद कृषि उत्पाद सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात में भी जो अवसर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों को उपलब्ध हैं, वो लैंड लॉक राज्यों को उपलब्ध नहीं है। बड़ा और विदेशी बाज़ार उपलब्ध न होने के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे सघन आबादी वाले राज्यों के किसानों के पास जोत भी छोटी होती है। कम जोत रखने वाले किसान भी कई फसलें या फल और सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर युवाओं को कोई संगठित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। केंद्र द्वारा कई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसका लाभ अंततः किसानों को मिलेगा। ❑

पुस्तक चर्चा

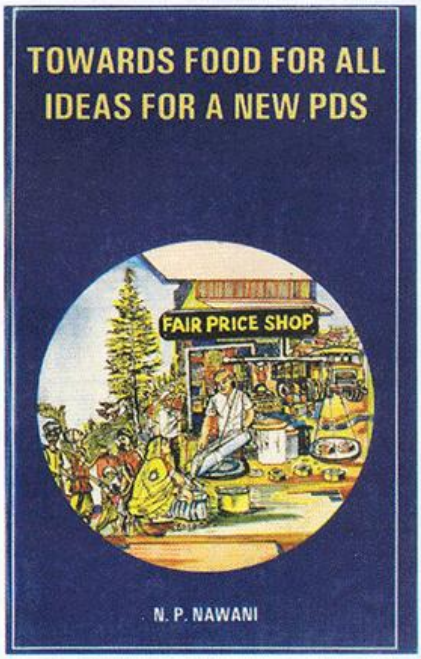

लेखक : एन.पी. नवानी
मूल्य : 100 रुपये, भाषा : अंग्रेजी

'टूवर्ड्स फूड फॉर ऑल आइडियाज़ फॉर ए न्यू पीडीएस' पुस्तक में लेखक ने पाठकों को भारत की खाद्य सुरक्षा सिद्धांत से परिचित कराने के बाद खाद्य नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पता लगाया है और इस प्रणाली में सुरक्षा सुधार सुनिश्चित कराने पर ध्यान दिलाया है।

पुस्तक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित करने के विभिन्न पहलुओं और खाद्यानों के आवंटन को तर्कसंगत बनाने तथा लक्षित पीडीएस के लिए खाद्य सब्सिडी के निहितार्थों पर चर्चा की गई है। ❑

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भूमि और लोग, कला और संस्कृति, वनस्पति और जीव, गांधीवादी साहित्य, जीवनियां और भाषण, विज्ञान और बाल साहित्य सहित राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रकाश डालने वाले प्रकाशनों की एक विस्तृत शृंखला देखने और खरीदने के लिए www.publicationsvision.nic.in पर देखें।